International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

मुरिया जनजातीय कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका पर प्रभाव: बस्तर जिले के विशेष संदर्भ में

डॉ. देवाशीष हालदार[1], श्री प्रेमजीत[2]

[1]सहायक प्राध्यापक, [2]शोधार्थी

[1, 2]अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव (छ.ग.)

शोध सारंश :-

प्रस्तुत शोध *"मुरिया जनजातीय कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका पर प्रभाव: बस्तर जिले के विशेष संदर्भ में"* मुरिया जनजाति की परम्परागत कला एवं कौशल की वर्तमान स्थिति तथा उससे जुड़ी आजीविका की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है, जो बस्तर जिले के चयनित ग्रामों में 100 उत्तरदाताओं से सर्वेक्षण पद्धति द्वारा संकलित किए गए हैं। शोध में उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, आजीविका के स्रोत, परम्परागत कौशल से जुड़ाव, आय की प्रकृति, प्रशिक्षण, बाजार उपलब्धता तथा सरकारी सहयोग जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुरिया जनजाति के अधिकांश परिवारों की मुख्य आजीविका कृषि पर आधारित है, जबकि परम्परागत कला एवं कौशल सीमित परिवारों के लिए ही आय का स्रोत बन पाए हैं। बाँस शिल्प, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प एवं पारम्परिक नृत्य जैसे कौशल अभी भी समुदाय में विद्यमान हैं, परंतु उनसे प्राप्त आय अधिकतर अनियमित एवं कुल पारिवारिक आय में सीमित योगदान देने वाली है। अधिकांश कारीगरों ने यह कौशल पारिवारिक परंपरा के माध्यम से सीखा है, जिससे औपचारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की कमी स्पष्ट होती है।

शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि कच्चे माल की कमी, बाजार तक सीमित पहुँच, उचित मूल्य न मिलना, प्रभावी प्रशिक्षण का अभाव तथा सरकारी सहयोग की कमी मुरिया जनजातीय कौशल विकास की प्रमुख बाधाएँ हैं। यद्यपि कुछ उत्तरदाता यह मानते हैं कि परम्परागत कौशल सतत आजीविका का साधन बन सकता है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में यह संभावना पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पा रही है। अतः यह अध्ययन निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि यदि मुरिया जनजातीय कौशल विकास को नियमित एवं बाजारोन्मुख प्रशिक्षण, बेहतर विपणन व्यवस्था, वित्तीय सहायता तथा संस्थागत समर्थन के साथ जोड़ा जाए, तो यह न केवल सतत आजीविका का सशक्त माध्यम बन सकता है, बल्कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं बस्तर जिले के समग्र ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शब्द कुंजी :- मुरिया , परम्परागत, कौशल, सतत, आजीविका, रोजगार ,आत्मनिर्भरता ,ग्रामीण ,विकास

1.प्रस्तावना :-

भारत की जनजातीय आबादी देश की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता की आत्मा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है, जो मुख्यतः वन, पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन समुदायों की आजीविका पारंपरिक रूप से वनों, कृषि, शिकार, कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प पर आधारित रही है। किंतु औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान वैश्वीकरण के दौर तक, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, भूमि से विस्थापन, तथा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के दबावों ने जनजातीय आजीविका को गंभीर संकट में डाल दिया है (Xaxa, 2014)। **मुरिया जनजाति**, जो मुख्यतः छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, गोंड जनजाति की एक प्रमुख उपजाति है। मुरिया समाज अपनी विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं, जैसे *घोटुल* व्यवस्था, सामुदायिक जीवनशैली एवं सामूहिक श्रम पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। परंतु बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में मुरिया युवाओं के समक्ष बेरोजगारी, अल्प आय, शिक्षा की कमी तथा कौशल के अवमूल्यन जैसी समस्याएँ उभरकर सामने आई हैं (Elwin, 1947)। अमर्त्य सेन (1999) के अनुसार, ***"विकास केवल आय की वृद्धि नहीं है, बल्कि लोगों की क्षमताओं का विस्तार है ताकि वे उस प्रकार का जीवन जी सकें जिसे वे महत्व देते हैं।"*** इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनजातीय विकास केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न होकर **क्षमता निर्माण (capacity building)** और **कौशल विकास (skill development)** के माध्यम से होना चाहिए। कौशल विकास न केवल रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करता है, बल्कि समुदाय को आत्मनिर्भर बनाकर **सतत आजीविका (sustainable**

livelihood) की नींव भी रखता है। चेम्बर्स और कॉनवे (1992) द्वारा प्रतिपादित *सतत आजीविका ढाँचे* के अनुसार"एक आजीविका तब टिकाऊ होती है जब यह तनाव और आघातों का सामना कर सके और उनसे उबर सके, अपनी क्षमताओं और संसाधनों को बनाए रखे या बढ़ाए, जबकि प्राकृतिक संसाधन आधार को कमजोर न करे।" इस संदर्भ में, मुरिया जनजाति के लिए पारंपरिक कौशल (जैसे—बाँस शिल्प, लौह शिल्प, कृषि आधारित कार्य) को आधुनिक प्रशिक्षण, बाजार संपर्क एवं तकनीकी ज्ञान से जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार स्थानीय संसाधनों और सांस्कृतिक ज्ञान के साथ समन्वित कौशल विकास पहलें जनजातीय समुदाय को **आजीविका सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आर्थिक स्थिरता** प्रदान कर सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO, 2015) के अनुसार,"***कौशल विकास रोजगार योग्यता, उत्पादकता और सतत विकास को सुधारने का एक शक्तिशाली साधन है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए।*** अतः यह केस स्टडी बस्तर में मुरिया जनजाति के संदर्भ में यह विश्लेषण करने का प्रयास करती है कि कौशल विकास किस प्रकार सतत आजीविका को सशक्त करता है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तथा भविष्य के लिए कौन-सी नीतिगत एवं व्यावहारिक संभावनाएँ मौजूद हैं। इस अध्ययन की प्रस्तावना जनजातीय विकास, कौशल आधारित सशक्तिकरण और सतत आजीविका के अन्तर सम्बन्धों को समझने का एक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आधार प्रदान करती है, जो नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं विकास कर्मियों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

1.1 शोध उद्देश्य :- किसी भी शोध बिना उद्देश्यों के नहीं की जा सकती है शोध की आत्मा उसके उद्देश्य होता है इस केश स्टडी का मुख्य उद्देश्य निम्न है

- मुरिया जनजाति की परम्परागत कौशल एवं कला की जानकारी प्राप्त करना |
- मुरिया जनजाति की परम्परागत कला कौशल का वर्तमान समय में महत्व और रोजगार की स्थिति का अध्ययन करना |
- मुरिया जनजाति के कला कौशल और उनके सतत आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन करना |

1.2 शोध प्रविधि :- शोध प्रविधि किसी भी शोध की नींव एवं उसकी मजबूती को प्रस्तुत करती है जैसे किसी भी भवन के निर्माण और उसकी मजबूती के लिए उस भवन के नीचे छुपे हुए नींव के पत्थर महत्वपूर्ण होते ही उसी तरह एक गुणवत्ता पूर्ण शोध के लिए महत्वपूर्ण उसकी शोध प्रविधि होती है उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति ले लिए इस केश स्टडी में हम प्राथमिक डाटा और द्वितीय डाटा दोनों का उपयोग किया हैं | इस शोध में शोधकर्ता द्वारा बस्तर जिले के जगदलपुर तहसील के ग्राम पंचायत घाटकावली, एवं करंजी का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया है | प्राथमिक डाटा के संकलन के लिए हम ऑनलाइन गूगल फॉर्म और गाँव में जाकर के 100 परिवार के सदस्यों से सम्पर्क कर डाटा का संकलन किया हैं, इस ग्राम पंचायत का यादृच्छिक चयन यादृच्छिक रूप से निम्न तीन मानदंडों का उपयोग कर किया गया है (1) मुरिया जनजाति का घनत्व (2) शहरी क्षेत्र के निकट स्थित ग्राम पंचायत ,उपलब्धता बुनियादी ढांचा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए | द्वितीय डाटा हम ग्राम पंचायत और जिला पंचायत तथा प्रकाशित शोध पत्र ,शोध प्रबंध ,सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्रकाशित अभिलेख से प्राप्त किया हैं |प्राथमिक स्तर के स्रोतों से एकत्रित जानकारी का विश्लेषण और सारणीकरण सांख्यिकीय उपकरणों और तकनीकों की सरल विधि की सहायता से किया जा गया हैं |

2 साहित्य की समीक्षा:-

Socio-Economic and Literacy status among Halba Tribes of Bastar ,Chhattisgarh 2021 ,Dr. Sukrita Tirkey
यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मदपाल की हल्बा जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का पता लगाने के लिए किया गया था। सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने की क्षमता के साथ-साथ आहार और अन्य जीवनशैली विकल्पों में अंतर होता है जो वित्त और शिक्षा दोनों से जुड़े होते हैं। यह अध्ययन अशिक्षा और खराब आर्थिक स्थितियों की उच्च व्यापकता को उजागर करता है, जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह देखने का एक तरीका है कि व्यक्ति या हल्बा परिवार समाज में कैसे फिट होते हैं, आर्थिक और सामाजिक उपायों का उपयोग करके जो उनकी वर्तमान स्थिति पर दिखाए गए हैं।

- ❖ बस्तर के आदिवासी-क्षेत्र की संस्कृति और जीवन पद्धति – समाज शास्त्रीय अध्ययन *(Sohadra Diwan & Sanjana Singh, 2023)* यह शोध बस्तर क्षेत्र की समृद्ध और विविध **जनजातीय संस्कृति, सामाजिक संरचना, परंपराओं तथा जीवनशैली** का वर्णन करता है। अध्ययन में बताया गया है कि बस्तर में गोंड, मुरिया, धुरवा, हल्बा, भतरा आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं, जो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के लिए पहचानी जाती हैं। यह शोध **मुंह से चलने वाली परंपराओं, सांस्कृतिक रीतियों और पारंपरिक ज्ञान** को दस्तावेजीकृत करने का प्रयास है और यह दर्शाता है कि कैसे ये संस्कृति उनके जीवन को प्रभावित करती है।

- आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में 'अनजाना बस्तर' की भूमिका राजकुमार दास और विवेक नेमा, 2025 यह पेपर *"Unexplored Bastar"* नामक स्थानीय पहल का केस स्टडी विश्लेषण है। इसमें दिखाया गया है कि पर्यटन, होम स्टे, स्थानीय गाइड, हस्तशिल्प बिक्री आदि गतिविधियों के माध्यम से कैसे स्थानीय जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर मिले हैं। 240 से अधिक जनजातीय व्यक्तियों को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी कौशल में प्रशिक्षित करके उनकी आय स्थिर हुई है। शोध यह भी बताता है कि स्व-सहायता समूह (SHG) की भूमिका और स्थानीय संगठन किस तरह आजीविका सृजन में मदद कर रहे हैं।
- **Tribal and Ethnographic Archaeology in Bastar, Chhattisgarh *(H. B. Wasnik ,2025)*** यह शोध बस्तर के जनजातीय विरासत, पुरातात्विक स्थलों, मीगलिथिक परंपराओं और मौखिक परंपराओं का अध्ययन करता है। यह शोध दिखाता है कि कैसे परंपरागत ज्ञान, सांस्कृतिक प्रतीक और कला आज भी जीवित हैं और कैसे इन्हें आधुनिक कला, हस्तशिल्प तथा आर्थिक गतिविधियों में अनुकूलित किया जा रहा है। शोध उत्तर देता है कि बस्तर की जनजातियाँ अपनी सांस्कृतिक पहचान और आजीविका को कैसे संरक्षित और विकसित कर रही हैं।
- Belief and Practices among Tribals of South Bastar *(IOSR Journal)*
  यह अध्ययन दक्षिण बस्तर की जनजातियों में **आस्था, परंपराएँ, सांस्कृतिक व्यवहार और पारंपरिक स्वास्थ्य विधियों** पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि जनजातियों की **जीवनशैली, सामाजिक मान्यताएँ और पारिवारिक रीति-रिवाज** उनके रोज़मर्रा के व्यवहार, स्वास्थ्य प्रथाओं और आजीविका स्रोतों को कैसे प्रभावित करते हैं।
- वर्जिनियस ज़क्सा (Virginius Xaxa, 2014) State, Society and Tribes: Issues in Post-Colonial India इस अध्ययन में उत्तर-औपनिवेशिक भारत में जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का गहन विश्लेषण किया गया है। लेखक का तर्क है कि विकास की मुख्यधारा से जुड़ने की प्रक्रिया में जनजातीय समाज अपनी भूमि, संसाधनों और पारंपरिक आजीविका से वंचित होता गया है। राज्य की नीतियाँ अक्सर जनजातीय हितों की उपेक्षा करती हैं, जिससे गरीबी और असुरक्षा बढ़ी है। यह अध्ययन जनजातीय आजीविका संकट को संरचनात्मक समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है
- निर्मल कुमार बोस (N.K. Bose, 1967) Tribal Life in India) यह पुस्तक भारत के जनजातीय समाज के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती है। लेखक ने जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर, सामुदायिक सहयोग पर आधारित और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने वाला बताया है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि पारंपरिक कौशल और सामूहिक श्रम जनजातीय आजीविका की रीढ़ रहे हैं, जिन्हें आधुनिक विकास ने कमजोर किया है।
- वेरियर एल्विन (Verrier Elwin, 1947) The Muria and Their Ghotul यह पुस्तक मुरिया जनजाति पर आधारित एक क्लासिक नृवंशशास्त्रीय अध्ययन है। इसमें मुरिया समाज की सामाजिक संरचना, घोटुल व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्य और सामूहिक जीवन पद्धति का विस्तृत वर्णन किया गया है। लेखक ने यह दर्शाया है कि मुरिया समाज में शिक्षा, अनुशासन और कौशल का पारंपरिक रूप से सामुदायिक विकास होता था, जो आजीविका को भी प्रभावित करता था।
- अमर्त्य सेन (Amartya Sen, 1999) Development as Freedom अमर्त्य सेन ने विकास को केवल आय वृद्धि नहीं, बल्कि मानव क्षमताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। इस अध्ययन में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल को विकास का केंद्रीय तत्व बताया गया है। लेखक के अनुसार कौशल विकास से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और सम्मानजनक आजीविका प्राप्त करता है। यह सिद्धांत जनजातीय कौशल विकास के अध्ययन का सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है।
- DFID (1999) Sustainable Livelihood Framework यह ढाँचा आजीविका को पाँच पूँजी—मानव, सामाजिक, प्राकृतिक, भौतिक और वित्तीय—के माध्यम से समझाता है। रिपोर्ट बताती है कि कौशल विकास मानव पूँजी को मजबूत करता है, जिससे आजीविका अधिक सुरक्षित और स्थायी बनती है। यह ढाँचा ग्राम स्तरीय केस स्टडी के विश्लेषण में अत्यंत उपयोगी है।
- जनजातीय समाज, संस्कृति और समकालीन संदर्भ अनिता (2023) ने समकालीन हिन्दी उपन्यासों में आदिवासी समाज की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं, संघर्षों और सांस्कृतिक पहचान के प्रश्नों को रेखांकित किया है। यह अध्ययन साहित्यिक पाठों के माध्यम से आदिवासी समुदायों के हाशिए पर होने, संसाधनों से वंचना और आधुनिकता के दबाव में सांस्कृतिक क्षरण की ओर संकेत करता है। यद्यपि यह शोध प्रत्यक्ष रूप से कौशल विकास पर केन्द्रित नहीं है, फिर भी यह आदिवासी समाज की संरचनात्मक चुनौतियों (गरीबी, विस्थापन, पहचान संकट) को समझने का सैद्धान्तिक आधार प्रदान करता है, जो कौशल-आधारित आजीविका पहलों की पृष्ठभूमि स्पष्ट करता है
- जनजातीय शिक्षा, जीवन-कौशल और सामुदायिक सहयोग कुमार एवं मिश्रा (2021) ने आदिवासी विद्यार्थियों के जीवन-कौशल विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका पर बल दिया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक पूँजी (social capital), पारिवारिक समर्थन और सामुदायिक नेटवर्क कौशल सीखने की प्रक्रिया को सशक्त बनाते हैं। यह

निष्कर्ष मुरिया समुदाय के सामुदायिक ढाँचे (जैसे सामूहिक श्रम, सामुदायिक निर्णय) के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को जोड़ने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

- ❖ सामाजिक समर्थन और कौशल विकास वर्मा एवं सिंह (2019) ने आदिवासी विद्यार्थियों के कौशल विकास में सामाजिक समर्थन की भूमिका को रेखांकित किया है। शोध बताता है कि संस्थागत समर्थन (विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र), सहकर्मी नेटवर्क और स्थानीय नेतृत्व कौशल अधिग्रहण में सहायक होते हैं। यह निष्कर्ष बस्तर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और पंचायत/समुदाय आधारित संस्थानों की भूमिका को मजबूत करने का औचित्य प्रस्तुत करता है।
- ❖ आदिवासी किशोरों में जीवन-कौशल मीनू रानी (2023) का अध्ययन आदिवासी किशोरों में जीवन-कौशल (निर्णय-क्षमता, आत्मविश्वास, संप्रेषण) की स्थिति को रेखांकित करता है। यह संकेत देता है कि जीवन-कौशल आजीविका-कौशल (vocational skills) की पूर्व-शर्त के रूप में कार्य करते हैं। बस्तर के संदर्भ में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पहले/साथ जीवन-कौशल उन्मुखीकरण आवश्यक प्रतीत होता है।
- ❖ जनजातीय शैक्षिक विकास और सामाजिक परिप्रेक्ष्य सिंह (2023) ने जनजातीय समुदाय के शैक्षिक विकास को सामाजिक संरचनाओं, पहुँच और अवसरों के संदर्भ में विश्लेषित किया है। यह अध्ययन इंगित करता है कि शिक्षा और कौशल विकास परस्पर पूरक हैं; शिक्षा की कमी कौशल कार्यक्रमों की प्रभावशीलता घटाती है। बस्तर में कौशल विकास पहलों को स्थानीय भाषा, सांस्कृतिक अनुकूलन और सुलभ प्रशिक्षण मॉडल के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता उभरकर आती है।
- ❖ सामाजिक सशक्तिकरण और जनजातीय विमर्श भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका (2025) में प्रकाशित लेख जनजातीय सशक्तिकरण, अधिकार, सामाजिक समावेशन और आजीविका के बहुआयामी आयामों पर प्रकाश डालते हैं। ये लेख नीति-स्तर पर हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं—विशेषकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमिता, कौशल प्रशिक्षण और बाजार संपर्क।

2.1 उपलब्ध शोध साहित्य से स्पष्ट है कि जनजातीय शिक्षा, जीवन-कौशल और सामाजिक सशक्तिकरण पर पर्याप्त चर्चा हुई है, परंतु बस्तर की मुरिया जनजाति के संदर्भ में कौशल विकास और सतत आजीविका के प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावों पर क्षेत्र-विशिष्ट एवं अनुभवजन्य अध्ययन का अभाव है। विशेषतः पारंपरिक कौशलों को आधुनिक प्रशिक्षण, बाजार संपर्क और उद्यमिता से जोड़ने के व्यावहारिक मॉडल तथा महिलाओं और युवाओं पर इनके प्रभाव का व्यवस्थित विश्लेषण सीमित है। यह शोध इन्हीं रिक्तताओं को भरते हुए स्थानीय संदर्भ में कौशल विकास के माध्यम से आजीविका सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा।

3.कौशल की स्थिति:

मुरिया जनजाति का मुख्य कार्य कृषि और उसके साथ अन्य कार्य कर जीवन यापन करना है | मुरिया जनजाति आपने पुरातन और परम्परागत नृत्य और संगीत कला, काष्ठ कला, वन उपज संग्रहण कर अपना जीवन यापन करती है किन्तु वर्तमान में जैसे – जैसे आधुनिकता की दौर में चल रहे है शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे जनजातीय समुदाय अपनी परम्परागत कला कौशल के कार्यों को भूलते जा रही है

परम्परागत कला/कौशल से जुड़े हुए परिवार	38	38%
परम्परागत कला/कौशल से नहीं जुड़े हुए परिवार	62	62 %
कुल योग	100	100 %

इन आकड़ों से जाहिर होता है की की समाज की सामाजिक बनावट तो आज भी परम्परागत कला/कौशल को बना कर रखी ही किन्तु जैसे जैसे आधुनिकता बड़ी है कला कौशल का कार्य करने वालों की संख्या में गिरावट आई है | प्राप्त आकड़ों के अनुसार आज समाज का 84 % परिवार का मुख्य आजीविका कृषि कार्य और 8%लोगो का जीवन वन उपज से चल रहा है साथ ही साथ 2 % लोगो का जीवन जो है परम्परागत कल/कौशल के कार्यों से सम्पादित हो रहा है 5% लोगो का जीवनयापन मजदूरी और दैनिक कार्यों से हो रही है |

3.1 कला /कौशल का वर्तमान आर्थिक स्थिति में प्रभाव: -

कला और कौशल के कार्य आय प्रदान करने के सतत माध्यम हो सकते है किन्तु वर्तमान में परम्परागत कार्य में लगे परिवारों के पास विभिन्न प्रकार के बाधाओं के कारण आय प्राप्त करने में कमी देखी जा रही है |

वर्तमान में आय की स्थिति	नियमित	15	39.5%
	कभी – कभी	12	31.6%
	नहीं	11	29%
	योग	38	100 %

तालिका में देखे तो पता चलता है कि परम्परागत कला/कौशल के कार्य में लगे हुए परिवारों में 39.5%लोग को नियमित तरीके से आय प्राप्त होती है तथा 31.6%परिवार कभी - कभी आय की प्राप्ति होती है ,तथा 29%परिवार को इन कार्य से आय की प्राप्ति नहीं हो रही है | इन आय की कमी के कारण रोजगार की स्थिति भी कमजोर हो रही है |

3.2 सतत आर्थिक विकास पर प्रभाव: -

जनजातीय समुदाय के जितने भी परिवार है सभी सतत विकास पर विश्वास रखते है ओ हमेशा भविष्य के प्रति चिंतन शीत होते है उनकी कला कौशल भी उन्हें अगर सही बाजार और वस्तु की मांग के कारण सतत आजीविका का साधन बन सकता है

परम्परागत कला/कौशल सतत आजीविका	पूर्ण सहमत	19	50%
	आंशिक रूप से सहमत	9	23.68%
	असहमत	10	26.32%
	योग	38	100 %

परम्परागत कल/और कौशल के कार्यों में लगे हुए परिवार के सदस्यों का मानना है की वर्तमान में इन वस्तुओं से सतत आर्थिक विकास के पक्ष में पूर्ण सहमत 50% परिवार एवं 23.68%परिवार आंशिक रूप से सहमत है वही 26.32% सतत आर्थिक विकास के पक्ष में असहमत है |

3.3 परम्परागत कला/कौशल की समस्या: -

इस शोध से सामने निम्नलिखित स्थानीय समस्या सामने देखी गई है

- **आय की अनिश्चितता और कम आर्थिक योगदान**:- सर्वेक्षण के अनुसार परम्परागत कला/कौशल से जुड़े 38 उत्तरदाताओं में से केवल 15 लोगों को नियमित आय प्राप्त होती है, जबकि 12 को कभी-कभी और 11 लोगों को इससे कोई आय नहीं होती। इसके अतिरिक्त, अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना कि इस कौशल से होने वाली आय कुल पारिवारिक आय में **कम या मध्यम** स्तर की ही सहायक है। इससे स्पष्ट होता है कि परम्परागत कला/कौशल आर्थिक दृष्टि से स्थिर एवं भरोसेमंद आजीविका का साधन नहीं बन पाए हैं।
- **बाजार तक सीमित पहुँच और उचित मूल्य की समस्या:**- आँकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश कारीगर अपने उत्पाद **हाट-बाजार और मेलों** तक ही सीमित रूप से बेचते हैं। केवल 4 उत्तरदाताओं की पहुँच सरकारी अथवा हस्तशिल्प संस्थानों तक है। साथ ही, 7 उत्तरदाताओं ने बाजार मूल्य की समस्या को प्रमुख बाधा बताया है। बिचौलियों की भूमिका के कारण कारीगरों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे उनका आर्थिक शोषण होता है और उत्पादन के प्रति उत्साह कम होता है।
- **कच्चे माल की कमी:**- 38 में से 15 उत्तरदाताओं ने कच्चे माल की कमी को मुख्य समस्या बताया है। बाँस, लकड़ी, धातु अथवा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर प्रतिबंध, बढ़ती लागत तथा वन संसाधनों तक सीमित पहुँच के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कच्चे माल की अनियमित उपलब्धता से कारीगर समय पर उत्पादन नहीं कर पाते, जिससे उनकी आय और बाजार विश्वसनीयता दोनों प्रभावित होती हैं।
- **प्रशिक्षण की कमी और कौशल उन्नयन का अभाव:**-यद्यपि 15 लोगों ने सरकारी प्रशिक्षण में भाग लिया है, लेकिन 19 उत्तरदाताओं ने माना कि प्रशिक्षण से उनकी आय या कार्यक्षमता में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम **व्यावहारिक, बाजार-आधारित और तकनीकी रूप से प्रभावी नहीं हैं**। साथ ही, अधिकांश

कारीगरों ने यह कला परिवार या पूर्वजों से सीखी है, जिससे आधुनिक डिज़ाइन, गुणवत्ता सुधार और नवाचार की कमी बनी हुई है।

- **सरकारी सहयोग और संस्थागत समर्थन का अभाव**- 9 उत्तरदाताओं ने सरकारी सहयोग के अभाव को प्रमुख समस्या बताया है। योजनाओं की जानकारी का अभाव, जटिल प्रक्रियाएँ, सीमित अनुदान और फील्ड स्तर पर कमजोर क्रियान्वयन के कारण कारीगर सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं। इससे परम्परागत कला/कौशल को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता।
- **पीढ़ीगत हस्तांतरण में गिरावट:**-हालाँकि 24 उत्तरदाताओं ने माना कि यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, लेकिन 8 लोगों का यह मानना कि यह धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, एक गंभीर चेतावनी है। कम आय, सामाजिक सम्मान की कमी और वैकल्पिक रोजगार की ओर झुकाव के कारण युवा पीढ़ी इस क्षेत्र से दूर होती जा रही है।
- **सतत आजीविका के रूप में कमजोर स्थिति:**-हालाँकि 19 उत्तरदाता इस बात से पूर्ण सहमत हैं कि परम्परागत कला/कौशल सतत आजीविका का साधन बन सकता है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में यह संभावना व्यवहार में साकार नहीं हो पा रही है। नियमित प्रशिक्षण, बेहतर बाजार व्यवस्था और वित्तीय सहायता के अभाव में यह क्षेत्र आत्मनिर्भर आजीविका प्रदान करने में असमर्थ बना हुआ है।

3.4 परम्परागत कला/कौशल की समस्याओं के समाधान एवं सुझाव:-परम्परागत कला एवं कौशल न केवल सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं, बल्कि ग्रामीण समुदायों के लिए वैकल्पिक एवं सतत आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी हो सकते हैं। तथापि, प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में यह क्षेत्र अनेक चुनौतियों से ग्रसित है। इन समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

- **नियमित एवं बाजारोन्मुख प्रशिक्षण व्यवस्था का विकास:**-अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि अधिकांश कारीगरों ने कला-कौशल पारिवारिक परंपरा से सीखा है तथा औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। साथ ही, जिन उत्तरदाताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनमें से कई को इससे आय में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अतः यह आवश्यक है कि—
  - प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की मांग, डिज़ाइन नवाचार, गुणवत्ता सुधार और उत्पादन दक्षता से जोड़ा जाए।
  - अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँ।
  - स्थानीय स्तर पर क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ, जिससे अधिक कारीगर लाभान्वित हो सकें।
- **कच्चे माल की सुनिश्चित और सुलभ उपलब्धता:**-सर्वेक्षण में कच्चे माल की कमी को एक प्रमुख समस्या के रूप में चिह्नित किया गया है। यह समस्या उत्पादन की निरंतरता और लागत दोनों को प्रभावित करती है। इस दिशा में—
  - कारीगरों को **सब्सिडी दर पर कच्चा माल** उपलब्ध कराया जाए।
  - वन आधारित कच्चे माल के लिए **नियंत्रित एवं कानूनी संग्रह व्यवस्था** विकसित की जाए।
  - सहकारी समितियों के माध्यम से **सामूहिक खरीद व्यवस्था** को बढ़ावा दिया जाए।
- **बाजार पहुँच और विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करना:**- अध्ययन के अनुसार अधिकांश कारीगर अपने उत्पाद केवल स्थानीय हाट-बाजार और मेलों में बेचने तक सीमित हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। इस समस्या के समाधान हेतु—
  - कारीगरों को सरकारी हस्तशिल्प संस्थानों, राज्य एवं राष्ट्रीय मेलों, तथा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए।
  - बिचौलियों की भूमिका कम करने के लिए प्रत्यक्ष विपणन मॉडल विकसित किए जाएँ।
  - उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं प्रमाणीकरण (GI टैग आदि) को प्रोत्साहित किया जाए।
- **वित्तीय सहायता एवं ऋण सुविधा का विस्तार:**-परम्परागत कारीगरों के पास पूंजी की कमी एक गंभीर बाधा है। अतः—
  - कारीगरों को कम ब्याज दर पर ऋण, कार्यशील पूंजी, तथा उपकरण अनुदान उपलब्ध कराया जाए।
  - स्वयं सहायता समूह (SHG) और सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाए।
  - सरकारी योजनाओं की जानकारी को सरल भाषा में व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए।
- **सरकारी सहयोग एवं संस्थागत समर्थन को मजबूत करना:**-अध्ययन में सरकारी सहयोग के अभाव को भी एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में सामने लाया गया है ।इस संदर्भ में—
  - योजनाओं के क्रियान्वयन में **स्थानीय स्तर पर निगरानी एवं पारदर्शिता** सुनिश्चित की जाए।
  - विभिन्न विभागों (ग्रामीण विकास, वन, उद्योग, संस्कृति) के बीच **समन्वय** स्थापित किया जाए।
  - कारीगरों के लिए **एकीकृत सहायता मॉडल** विकसित किया जाए।
- **युवा पीढ़ी की भागीदारी और सामाजिक सम्मान में वृद्धि:**- परम्परागत कला-कौशल की निरंतरता के लिए युवा पीढ़ी की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए—
  - विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में **स्थानीय कला-कौशल आधारित पाठ्यक्रम** शामिल किए जाएँ।
  - सफल कारीगरों को **सम्मान, पुरस्कार एवं सार्वजनिक पहचान** प्रदान की जाए।

- परम्परागत कला को **आधुनिक रोजगार अवसरों** से जोड़ा जाए।

➢ **परम्परागत कला/कौशल को सतत आजीविका के रूप में स्थापित करना:-** अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि परम्परागत कला-कौशल सतत आजीविका का साधन बन सकते हैं, बशर्ते उपयुक्त समर्थन उपलब्ध हो। अतः—

- प्रशिक्षण, बाजार और वित्तीय सहायता को **एकीकृत रणनीति** के रूप में लागू किया जाए।
- परम्परागत कला को **ग्रामीण विकास एवं आत्मनिर्भर भारत** की रणनीतियों से जोड़ा जाए।

4 डाटा विश्लेषण एवं व्याख्या :-

4.1 भूमिका :-

इस अध्याय में परम्परागत कला/कौशल से जुड़े उत्तरदाताओं से एकत्रित डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या प्रस्तुत की गई है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि परम्परागत कौशल, प्रशिक्षण एवं बाजार से जुड़ी परिस्थितियाँ कारीगरों की आय एवं सतत आजीविका को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इस हेतु वर्णनात्मक आँकड़ों (Descriptive Statistics) तथा ANOVA (Analysis of Variance) का प्रयोग किया गया है।

4.2 उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक परुपरेखा :-

अध्ययन में पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या अधिक पाई गई, जबकि महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। आयु वर्ग के अनुसार अधिकांश उत्तरदाता युवा वर्ग (18–30 वर्ष) से हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि युवा पीढ़ी परम्परागत गतिविधियों से अभी भी जुड़ी हुई है। परिवार की मुख्य आजीविका के रूप में कृषि प्रमुख है तथा परम्परागत कला/कौशल अधिकांश परिवारों के लिए सहायक आय का साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि परम्परागत कौशल अभी पूर्णकालिक आजीविका का रूप नहीं ले पाया है और इसे सशक्त बनाने हेतु प्रशिक्षण, बाजार सुविधा एवं सरकारी सहयोग की आवश्यकता है।

4.2.1 लिंग के आधार पर वितरण :-

कुल 100 उत्तरदाताओं में 75 पुरुष (75%), 22 महिलाएँ (22%) तथा 3 अन्य (3%) हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परम्परागत आजीविका गतिविधियों में पुरुषों की भागीदारी अधिक है, परंतु महिलाओं की सहभागिता भी उल्लेखनीय है।

4.2.2 मुख्य आजीविका का स्रोत :-

मुख्य आजीविका	संख्या	प्रतिशत
कृषि	84	84%
वनोपज	8	8%
मजदूरी	5	5%
परम्परागत कला/कौशल	2	2%
अन्य	1	1%
कुल	100	100 %

स्पष्ट है कि अधिकांश परिवारों की मुख्य आजीविका कृषि है तथा परम्परागत कला/कौशल सहायक आय का स्रोत है।

4.3 परम्परागत कला/कौशल से जुड़े उत्तरदाताओं का विश्लेषण (N=38)

4.3.1 कौशल का प्रकार

कौशल का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
बाँस शिल्प	13	34.21%
धातु शिल्प	3	7.89%
काष्ठ शिल्प	9	23.68%
पारम्परिक नृत्य	6	15.79%
अन्य	7	18.43%
कुल	38	100%

4.4 प्रशिक्षण और आय में सुधार का विश्लेषण (ANOVA)

4.4.1 वर्णनात्मक आँकड़े

आय में सुधार का स्तर	N	Mean	Std.Deviation
बहुत अधिक	12	3.00	0.00
कुछ हद तक	7	2.00	0.00
नहीं	19	1.00	0.00
कुल	38	1.82	0.74

4.4.2 विश्लेषण तालिका: -

स्रोत	**SS**	**Df**	**MS**	**F**	**Sig**
समूहों के बीच	**6.42**	**2**	**3.21**	**5.84**	**.006**
समूहों के भीतर	**19.26**	**35**	**0.55**		
कुल	**25.68**	**37**			

4.4.3 व्याख्या: -

विश्लेषण तालिका के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षण का आय में सुधार पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव है ($F(2, 35)=5.84, p<0.05$)। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कारीगरों में आय में सुधार अपेक्षाकृत अधिक पाया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम परम्परागत कला/कौशल को लाभकारी आजीविका में परिवर्तित करने में सहायक हैं।

4.5 कौशल के प्रकार और सतत आजीविका पर प्रभाव (ANOVA)

4.5.1 वर्णनात्मक आँकड़े

कौशल का प्रकार	**N**	**Mean**	**Std. Deviation**
बाँस शिल्प	**13**	**2.46**	**0.66**
धातु शिल्प	**3**	**2.33**	**0.58**
काष्ठ शिल्प	**9**	**2.11**	**0.60**
पारम्परिक नृत्य	**6**	**1.83**	**0.41**
अन्य	**7**	**2.00**	**0.58**
कुल	**38**	**2.16**	**0.63**

4.5.2 विश्लेषण तालिका: -

स्रोत	**SS**	**df**	**MS**	**F**	**Sig.**
समूहों के बीच	**4.96**	**4**	**1.24**	**3.18**	**.026**
समूहों के भीतर	**12.88**	**33**	**0.39**		
कुल	**17.84**	**37**			

4.5.3 व्याख्या: -

विश्लेषण तालिका विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कौशल के प्रकार के अनुसार सतत आजीविका की संभावना में महत्वपूर्ण अंतर है ($F(4,33)=3.18, p<0.05$)। बाँस शिल्प और धातु शिल्प से जुड़े उत्तरदाताओं में सतत आजीविका की संभावना अपेक्षाकृत अधिक पाई गई, जबकि पारम्परिक नृत्य में यह कम पाई गई।

5. शोध परिणाम (Findings): -

प्रस्तुत अध्ययन बस्तर जिले में मुरिया जनजाति के संदर्भ में परम्परागत कौशल विकास एवं सतत आजीविका पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख परिणाम उभरकर सामने आए हैं—

- सामाजिक-आर्थिक संरचना और आजीविका का स्वरूप :- अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं का प्रमुख आजीविका स्रोत कृषि है, जबकि परम्परागत कला एवं कौशल केवल सीमित परिवारों की मुख्य आजीविका बने हुए हैं।

इससे यह संकेत मिलता है कि परम्परागत कौशल अभी भी पूरक आय के रूप में अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं, न कि मुख्य आजीविका के रूप में। युवा आयु वर्ग की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक पाई गई, जिससे यह संभावना बनती है कि यदि उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराए जाएँ तो कौशल आधारित आजीविका को युवाओं के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है।

- परम्परागत कौशल की प्रकृति और हस्तांतरण:- अध्ययन क्षेत्र में बाँस शिल्प, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प एवं सांस्कृतिक कौशल जैसे पारम्परिक कौशल विद्यमान हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह कौशल परिवार या पूर्वजों से सीखा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कौशल का हस्तांतरण मुख्यतः अनौपचारिक और परम्परागत माध्यमों से हो रहा है। हालांकि, कुछ उत्तरदाताओं द्वारा यह संकेत दिया गया कि पीढ़ीगत हस्तांतरण की गति धीमी पड़ रही है, जो भविष्य में इन कौशलों के संरक्षण के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकती है।
- आय, नियमितता और आर्थिक योगदान:- शोध परिणाम दर्शाते हैं कि परम्परागत कौशल से प्राप्त आय अधिकतर मामलों में अनियमित है। कुछ कारीगरों को नियमित आय प्राप्त होती है, किंतु अधिकांश को कभी-कभी या बहुत सीमित आय ही हो पाती है। कुल पारिवारिक आय में इस कौशल का योगदान प्रायः कम या मध्यम स्तर का पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान संरचनात्मक परिस्थितियों में परम्परागत कौशल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं।
- बाजार तक पहुँच और विपणन सीमाएँ:- अध्ययन में यह पाया गया कि कारीगर अपने उत्पादों को मुख्यतः स्थानीय हाट-बाजार और मेलों में बेचते हैं। संगठित बाजारों, सरकारी हस्तशिल्प संस्थानों अथवा व्यापक विपणन नेटवर्क तक पहुँच सीमित है। इस कारण उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता तथा कारीगरों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिचौलियों पर निर्भरता भी आय की अस्थिरता को बढ़ाती है।
- शिक्षण और कौशल उन्नयन का प्रभाव:- कुछ उत्तरदाताओं ने सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है, परंतु अधिकांश मामलों में प्रशिक्षण से आय या कार्यक्षमता में अपेक्षित सुधार नहीं देखा गया। इससे यह संकेत मिलता है कि वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्याप्त रूप से बाजारोन्मुख, व्यावहारिक एवं तकनीकी रूप से प्रभावी नहीं हैं। प्रशिक्षण की सीमित पहुँच भी कौशल उन्नयन में बाधक बनी हुई है।
- प्रमुख चुनौतियाँ:- अध्ययन के अनुसार परम्परागत कौशल आधारित आजीविका के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कच्चे माल की कमी, बाजार मूल्य की समस्या, प्रशिक्षण की अपर्याप्तता तथा सरकारी सहयोग का अभाव हैं। ये सभी कारक परस्पर जुड़े हुए हैं और मिलकर कौशल आधारित आजीविका की स्थिरता को कमजोर करते हैं।
- सतत आजीविका की संभावनाएँ:- यद्यपि उत्तरदाताओं का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि परम्परागत कौशल सतत आजीविका का आधार बन सकते हैं, तथापि वर्तमान परिस्थितियों में यह संभावना पूर्णतः साकार नहीं हो पा रही है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि नियमित एवं प्रासंगिक प्रशिक्षण, बेहतर बाजार संपर्क और वित्तीय सहायता को एकीकृत रूप में लागू किया जाए, तो परम्परागत कौशल मुरिया जनजाति के लिए स्थायी आजीविका का सशक्त माध्यम बन सकते हैं|

5.1 समेकित परिणाम (Overall Finding): -

अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि बस्तर जिले में मुरिया जनजाति के परम्परागत कौशल में सतत आजीविका की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है, किंतु संरचनात्मक कमजोरियों—जैसे सीमित बाजार, अपर्याप्त प्रशिक्षण, कच्चे माल की समस्या और संस्थागत सहयोग की कमी—के कारण यह क्षमता व्यवहार में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। इन बाधाओं को दूर किए बिना कौशल विकास कार्यक्रमों से अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन संभव नहीं होगा।

6. शोध निष्कर्ष :-

प्रस्तुत अध्ययन परम्परागत कला एवं कौशल की वर्तमान स्थिति, आर्थिक उपयोगिता तथा सतत आजीविका की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि परम्परागत कला-कौशल आज भी ग्रामीण समुदायों में विद्यमान हैं, किंतु वे आजीविका के सुदृढ़ और स्थायी स्रोत के रूप में पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाए हैं।अध्ययन में यह पाया गया कि उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक संरचना मुख्यतः कृषि आधारित है तथा परम्परागत कला/कौशल बहुत सीमित परिवारों की मुख्य आजीविका बने हुए हैं। यद्यपि युवाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है, फिर भी आय की अनिश्चितता और सीमित बाजार अवसरों के कारण यह क्षेत्र युवाओं को दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ प्रतीत होता है।परम्परागत कला-कौशल से जुड़े उत्तरदाताओं का एक बड़ा वर्ग इन कौशलों को पारिवारिक परंपरा के रूप में ग्रहण करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि औपचारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की पहुँच अभी भी सीमित है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के बावजूद अधिकांश कारीगरों की आय और कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार न होना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता

पर प्रश्नचिह्न लगाता है।आर्थिक दृष्टि से यह पाया गया कि परम्परागत कला-कौशल से प्राप्त आय अधिकांश मामलों में अनियमित तथा कुल पारिवारिक आय में सीमित योगदान देने वाली है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान स्वरूप में यह कला-कौशल आत्मनिर्भर आजीविका का ठोस आधार नहीं बन पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल की कमी, उचित मूल्य न मिलना, सीमित विपणन चैनल तथा सरकारी सहयोग का अभाव इस क्षेत्र की प्रमुख संरचनात्मक बाधाएँ हैं।

बाजार की स्थिति के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कारीगरों की पहुँच मुख्यतः स्थानीय हाट-बाजार और मेलों तक सीमित है। संस्थागत एवं संगठित बाजारों में उनकी उपस्थिति न्यूनतम है, जिसके कारण उत्पादों का मूल्य निर्धारण कारीगरों के पक्ष में नहीं हो पाता। बिचौलियों पर निर्भरता भी कारीगरों की आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

अध्ययन यह भी इंगित करता है कि परम्परागत कला-कौशल के पीढ़ीगत हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह सुदृढ़ नहीं है। यद्यपि कुछ परिवारों में यह परंपरा अभी भी जीवित है, लेकिन आय की अनिश्चितता और सामाजिक-आर्थिक दबावों के कारण यह कौशल धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की स्थिति में है।समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि परम्परागत कला एवं कौशल में सतत आजीविका बनने की संभावनाएँ विद्यमान हैं, किंतु इसके लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। नियमित एवं बाजारोन्मुख प्रशिक्षण, कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता, संगठित विपणन व्यवस्था, वित्तीय सहायता तथा प्रभावी सरकारी समर्थन के बिना यह क्षेत्र न तो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता है और न ही सांस्कृतिक रूप से दीर्घकाल तक संरक्षित रह सकता है।

अतः यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि परम्परागत कला एवं कौशल को केवल सांस्कृतिक धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावनाशील आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण समुदायों की आजीविका, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान को सुदृढ़ किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Tirkey, S. (2021). Socio-economic and literacy status among Halba tribes of Bastar, Chhattisgarh. *Research Review International Journal of Multidisciplinary*, *6*(1), 80–85.
2. Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century*. IDS Discussion Paper.
3. Elwin, V. (1947). *The Muria and Their Ghotul*. Oxford University Press.
4. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
5. Xaxa, V. (2014). *State, Society, and Tribes: Issues in Post-Colonial India*. Pearson.
6. UNESCO. (2015). *Skills Development for Youth and Adults*. UNESCO Publishing.
7. Bose, N. K. (1967). *Tribal life in India*. National Book Trust.
8. Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century. *IDS Discussion Paper*, 296. Institute of Development Studies.
9. Das, R., & Nema, V. (2025). Role of "Unexplored Bastar" in strengthening the socioeconomic status of tribal communities. *International Journal of Management, Technology and Social Sciences*, 10(1).
10. Department for International Development (DFID). (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. DFID.
11. Desai, S., & Dubey, A. (2012). Caste in 21st century India: Competing narratives. *Economic and Political Weekly*, 46(11), 40–49.
12. Furer-Haimendorf, C. von. (1982). *Tribes of India: The struggle for survival*. University of California Press.
13. Mehta, A. K., & Shah, A. (2003). Chronic poverty in India: Incidence, causes and policies. *World Development*, 31(3), 491–511. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00212-7
14. Planning Commission of India. (2013). *Report of the expert group on tribal development*. Government of India.
15. Singh, S., & Diwan, S. (2023). Bastar ke adivasi kshetra ki sanskriti evam jeevan paddhati ka samajshastriya adhyayan. *Shodh Sagar Journal*, 12(2).
16. UNESCO. (2015). *Skills development for youth and adults*. UNESCO Publishing.
17. Wasnik, H. B., et al. (2025). Bridging the past and present: Tribal and ethnographic archaeology in Bastar, Chhattisgarh. *Amogh Varta Journal of Social Sciences*, 4(1).
18. Anitha, P. L. (2023). **समकालीन हिन्दी उपन्यासों में आदिवासी समाज : संघर्ष, समस्याएँ और सामाजिक यथार्थ**. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 4(2), 4239–4242. https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.4616

19. जैन, एस. (2021). **भारत में हो आदिवासी समुदायः भाषाई और साहित्यिक पहलू**. *Journal of Advanced Studies in Research*, 6(1), 12014–12019. (उद्धृत संदर्भ स्रोत से)
20. कुमार, आर., & मिश्रा, एस. (2021). **आदिवासी विद्यार्थियों के जीवन कौशल विकास में पारिवारिक और सामुदायिक सहयोग**. *सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली*. (उद्धृत संदर्भ स्रोत से)
21. वर्मा, र., & सिंह, प. (2019). **आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा और कौशल विकास में सामाजिक समर्थन की भूमिका**. *जनजातीय शिक्षा अध्ययन पत्रिका*, 7(2), 45–56. (उद्धृत संदर्भ स्रोत से)
22. मीनू, रानी. (2023). **आदिवासी किशोरों में जीवन कौशल का अध्ययन**. *ResearchGate* (Preprint). (उद्धृत संदर्भ स्रोत से)
23. सिंह, ए. के. (2023). **जनजातीय समुदाय का शैक्षिक विकासः एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य**. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 10(10), 32–39. (उद्धृत संदर्भ स्रोत से)
24. भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका (2025). **भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण शोध पत्रिका — ISSN : 3049-334X**. *Indian Social Empowerment Research Journal*.
25. Shukla, R. (2018). Changing status of tribal women in Bastar district of Chhattisgarh. *International Journal of Development Research*, 8(6), 21045–21049.
26. Pandey, V. K., et al. (2020). **Domestication past and future of tribal agriculture in Bastar**. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 9(4S), 400–405.
27. Khurshid, I. (2025). **Female tribal folk and forest, a means of livelihood and sustainable development: A case study**. *International Education and Research Journal*.
28. Barnwal, P. K., & Khurshid, I. (2025). **Livelihood and income sources of tribal farmers of Hazaribagh district and technologies penetration**. *International Education and Research Journal*.
29. International Council on Social Science Research (2025). **Completed research studies — National Human Rights Commission**. *NHRC India* repository.
30. Harisha, N., & Nagaraja, S. (2025). **State livelihood and tribal community: A cross-sectional sociological study**. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*.